



Neutral Citation No. - 2026:AHC:11512

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - सी - 88 वर्ष 2026

नरेंद्र प्रसाद

.....याचिकाकर्ता

बनाम

अतिरिक्त आयुक्त (न्यायिक-प्रथम) और अन्यप्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: उमा शंकर वर्मा, योगेंद्र कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

5. उपरोक्त आदेश पारित होने के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की है क्योंकि यह उचित नहीं है। 1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की गई है:-

"1). परमादेश के स्वरूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें अतिरिक्त आयुक्त (न्यायिक-प्रथम), वाराणसी प्रभाग, वाराणसी/प्रतिवादी संख्या 1 को अपील/मामला संख्या 1478/2025, कम्प्यूटरिकृत मामला संख्या C202514000001478 - दयाराम पटेल बनाम नरेंद्र प्रसाद और अन्य) का निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया जाए, जो उनके समक्ष लंबित है।

3. इस याचिका में पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस भेजकर और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखकर कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रतिवादी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



इस आदेश से असंतुष्ट है, तो उसे आदेश में पुनरीक्षण/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि मामला लंबे समय से लंबित है। उनका तर्क है कि काफी समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह याचिका संबंधित प्राधिकारी को निर्देश देते हुए निपटाई जाती है कि वह उपरोक्त मुकदमे का फैसला कानून के अनुसार, अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से चार महीने की अवधि के भीतर करे। लेकिन सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडेया)

16 जनवरी, 2026

ऐमन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"